बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 135 ● नई दिल्ली ● बुधवार 11 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

## ईंधन आपूर्ति पर केजरीवाल का बड़ा हमला, पीएम मोदी, ट्रम्प के आगे झुके, देश चुका रहा कीमत

नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष से भू-राजनीतिक उथल-पुथल जारी है, जिससे वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है। इसी बीच, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दावा किया कि देशभर में कई प्रतिष्ठानों को एलपीजी की आपूर्ति रोक दी गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अपने मजबूरी के चलते ट्रम्प के सामने झुकने का आरोप लगाया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हालिया बयान के जवाब में एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश भर में, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को छोड़कर, अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एलपीजी गैस की आपूर्ति रोक दी गई है।

# चीन समेत पड़ोसी देशों के लिए एफडीआई नियमों में ढील, 8.8 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, चीन सहित भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को आसान बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इस बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत का चीन के साथ व्यापारिक घाटा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अहम फैसले के तहत सरकार ने 2020 में जारी प्रेस नोट 3 के प्रावधानों में ढील दी है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए यह सख्त नियम लागू किया गया था। पुराने नियमों के अनुसार, भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों- चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान- से आने वाले किसी भी निवेश के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी। गौरतलब है कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में भारी तनाव आ गया था। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने टिकटॉक, वीचैट और यूसी ब्राउजर जैसे 200 से अधिक चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था।

**कैबिनेट ने 8.8 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी दी हरी झंडी**

देश में रणनीतिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए भी केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एजेंडा 2024 के तहत कैबिनेट ने कुल 8.8 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। इन फैसलों में रेलवे, हाईवे, एविएशन और ग्रामीण जल आपूर्ति जैसे प्रमुख सेक्टर्स शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्था को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

**जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी**

कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए कुल 8.8 लाख करोड़ रुपये के फंड में से सबसे बड़ा हिस्सा बुनियादी जरूरतों और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। सरकार ने जल जीवन मिशन के विस्तार के लिए 8.7 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

**कनेक्टिविटी और यातायात सुविधाओं का विस्तार**

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और परिवहन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने कई प्रमुख रेलवे और सड़क परियोजनाओं के साथ-साथ विमानन क्षेत्र के लिए अहम फैसले लिए हैं-

**एविएशन सेक्टर**- एक प्रमुख नीतिगत फैसले के तहत मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट (अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) घोषित किया गया है।

**रोड नेटवर्क** - जेवर एयरपोर्ट और फरीदाबाद सेक्शन को जोड़ने वाले एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 3,631 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, बदनावर-थांदला-टिमरवानी राजमार्ग को 4-लेन बनाने के लिए 3,839 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

**रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर** - रेल यातायात की भीड़ कम करने और माल ढुलाई को तेज करने के लिए संतरागाछी-खड़गपुर के बीच चौथी लाइन बिछाने के लिए 2,905 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

इसी तरह सैथिया-पाकुड़ के बीच चौथी रेलवे लाइन के लिए 1,569 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। भले ही सरकार ने अब नियमों में ढील दी है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारत में चीनी निवेश का हिस्सा बहुत कम रहा है।

अप्रैल 2000 से दिसंबर 2021 के बीच भारत में हुए कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में चीन की हिस्सेदारी मात्र 0.43 फीसदी (2.45 बिलियन डॉलर) रही है।

**बढ़ता व्यापार**- न्यूनतम निवेश के बावजूद, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कई गुना बढ़ा है और बीजिंग भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है।

**आयात-निर्यात**- वर्ष 2024-25 में चीन से भारत का आयात 11.52फीसदी बढ़कर 113.45 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि निर्यात 14.5फीसदी घटकर 14.25 बिलियन डॉलर रहा।

वर्तमान रुझान- चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-जनवरी 2025-26) के दौरान चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में 38.37फीसदी का भारी उछाल आया है (15.88 बिलियन डॉलर), वहीं आयात भी 13.82फीसदी बढ़कर 108.18 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। इस अवधि में व्यापार घाटा 92.3 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया है।

**अन्य महत्वपूर्ण फैसले**

एफडीआई नियमों में ढील देने के साथ-साथ, कैबिनेट ने कॉरपोरेट सेक्टर को राहत देने वाले दो अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंजूरी दी है। दिवाला प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) बिल 2025 में संशोधनों को मंजूरी दी गई है। यह बदलाव सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। इसके अलावा, कंपनियों के कामकाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक को भी हरी झंडी दी गई है।

# आबकारी नीति मामला- सीबीआई के बाद अब ईडी भी पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, 19 मार्च को होगी सुनवाई

नई दिल्ली । आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय भी ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग को लेकर लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मांग की है कि 27 फरवरी के आदेश में उसके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दिया जाए। इस मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। ईडी की अर्जी पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सुनवाई की। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने जिस मामले में एजेंसी के खिलाफ टिप्पणियां की हैं उस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का कोई कंसर्न नहीं है। न्यायाधीश ने बिना एजेंसी को सुने टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी टिप्पणियां करनी भी थीं, तो अदालत को पहले एजेंसी का पक्ष सुनना चाहिए था। दिल्ली हाई कोर्ट ने

ईडी की याचिका पर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, जिनमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है।

**केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 लोगों को नोटिस**

बता दें कि आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और इसके जांच अधिकारी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों और जांच अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश पर सोमवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में 16 मार्च को सुनवाई होगी।

**ईडी की दिल्ली हाईकोर्ट से अपील**

ईडी ने अपनी अर्जी में कहा है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां बहुत यादा और बेवजह की गई हैं। यह भी तर्क दिया है कि अदालत ने अंदाजे के आधार पर बिना उसका पक्ष सुने पीठ पीछे से तल्ख टिप्पणियां की हैं। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है कि वह उसकी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बारे में ट्रायल कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों को हटा दे। ट्रायल कोर्ट ने ये टिप्पणियां हाल ही में सीबीआई के आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत 23 अन्य को आरोपमुक्त करते हुए की थीं।

ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि 27 फरवरी का ट्रायल कोर्ट का आदेश साफ तौर पर न्यायिक दखलंदाजी का मामला है, क्योंकि कोर्ट ने उसके खिलाफ सख्त टिप्पणी करने से पहले न तो एजेंसी के सबूतों की जांच की और न ही उसके पक्ष को सुना। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का आरोपपत्र आम आदमी पार्टी की सरकार की 2021 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित गड़बड़ियों से जुड़ी है। सीबीआई और ईडी ने इस मामले की अलग-अलग जांच की। विशेष जज जितेंद्र सिंह की कोर्ट ने पीएमएलए और ईडी की जांच के बारे में कई सख्त बातें कही थीं।

## कंबाला से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, कहा सिर्फ खास इलाकों तक ही क्यों रखें संस्कृति

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक में कंबाला के आयोजन को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी ज़िलों के अलावा दूसरे हिस्सों में भैंसों की दौड़ का खेल कंबाला आयोजित करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पूछा कि इसे सिर्फ़ राय के एक खास इलाके तक ही क्यों सीमित रखा जाए। कर्नाटक में नवंबर और मार्च के बीच होने वाली कंबाला दौड़ में भैंसों की एक जोड़ी को हल से बांधा जाता है और एक व्यक्ति उसे नियंत्रित करता है। इस प्रतिस्पर्धा में उन्हें एक कीचड़ से भरे ट्रैक में एक साथ दौड़ाया जाता है, जिसमें सबसे तेज़ दौड़ने वाली टीम जीतती है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के 14 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने राय को दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के दो ज़िलों के बाहर किसी भी जगह को कंबाला के आयोजन के लिए सूचित करने से रोकने की अर्ज़ी को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस मेहता ने कहा अगर वे राय के अलग-अलग हिस्सों में संस्कृति दिखाना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? राय के दूसरे हिस्सों के लोगों को भी संस्कृतिसे परिचित होने दें। इसे सिर्फ़ एक खास इलाके तक ही क्यों सीमित रखा जाए? पेटा इंडिया की ओर से पेश वकील ने राय द्वारा पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे का जिक्र किया, जो उस समय कंबाला से जुड़ी याचिकाओं पर विचार कर रहा था। वकील ने कहा कि उस हलफनामे में, राय ने कहा था कि यह एक ऐसा खेल है जो कर्नाटक के दो तटीय जिलों में पारंपरिक है। वकील ने तर्क दिया इसका बेंगलुरु की परंपरा और संस्कृति से कोई लेना-देना नहीं है और कहा कि अब, यह कार्यक्रम राय की राजधानी के एक मैदान में होगा। याचिका खारिज करते हुए, बेंच ने कहा, इनमें से किसी दिन, हम पेटा से भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मई 2023 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान बेंच ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के संशोधन कानूनों की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें बैलों को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू, बैलगाड़ी दौड़ और भैंसों की दौड़ वाले खेल कंबाला को इजाज़त दी गई थी, और कहा कि ये वैध कानून हैं।

# स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महिलाओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक भूमिका निभाई- मुख्यमंत्री

नई दिल्ली ।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को चिकित्सा क्षेत्र में महिलाएं (बहु-विशेषज्ञता सम्मेलन) कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महिलाओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महिलाएं चिकित्सा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में योगदान दे रही हैं - डॉक्टर, सर्जन, शोधकर्ता, नर्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में। उन्होंने कहा कि उनका काम केवल रोगियों का इलाज करने तक ही सीमित नहीं है; यह एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाएं जिस संवेदनशीलता, करुणा और समर्पण के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करती हैं, वह इसे अधिक मानवीय बनाती है। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ डॉक्टरों, चिकित्सा विशेषज्ञों, नर्सिंग स्टाफ और बड़ी संख्या में महिला स्वास्थ्य पेशेवरों ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते

हुए गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, जागरूकता कार्यक्रमों और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक महिला को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि यह सरकार अमेरिका के इशारे पर चल रही है। अगर अमेरिका कहता है कि यह तेल ले लो, तो वे ले लेंगे, और अगर वह कहता है कि किसी जगह से तेल मत लो, तो वे नहीं लेंगे। अंततः, देश जिस असुरक्षा का सामना कर रहा है, वह पूरी तरह से भाजपा की वजह से है। इससे पहले 5 मार्च को राहुल गांधी ने कहा था कि आगे तूफानी समुद्र है, क्योंकि भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है। उन्होंने कहा कि ऐसे संकट में प्रधानमंत्री की चुप्पी यह साबित करती है कि कैसे एक समझौतावादी प्रधानमंत्री ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को त्याग दिया है। गांधी ने एक्स पर लिखा कि दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है।

आगे कठिन परिस्थितियाँ हैं। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है, क्योंकि हमारे आयात का 40फीसदी से अधिक हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। एलपीजी और एलएनजी के लिए स्थिति और भी खराब है। संघर्ष हमारे पड़ोस तक पहुँच गया है, हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है। फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि अधिनियम लागू करने से प्राकृतिक गैस वितरण के लिए एक स्पष्ट प्राथमिकता सूची तैयार हो गई है, जिससे वर्तमान आपूर्ति संबंधी बाधाओं का प्रबंधन किया जा सके।

# दिल्ली के खेड़ा खुर्द में नहर किनारे खड़ी कार से मिले दो शव, दम घुटने से मौत की आशंका

**बाहरी दिल्ली।** बाहरी उत्तरी दिल्ली के खेड़ा खुर्द इलाके में सड़क किनारे खड़ी एक कार के अंदर दो लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, थाना एनआईए क्षेत्र में मंगलवार को सूचना मिली कि सड़क किनारे नहर के पास खड़ी एक कार के अंदर दो लोग पड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

वहां एक सफेद रंग की ऑरा कार (नंबर यूपी-27 CT-7719) खड़ी मिली, जिसकी खिड़कियां बंद थीं और कार लॉक नहीं थी। पुलिस ने जब कार की जांच की तो अंदर से बदबू आ रही थी। कार के अंदर दो लोग बैठे हुए मृत अवस्था में मिले। कार के भीतर शराब के तीन पाउच भी मिले, जिनमें दो सील बंद और एक खुला हुआ था। जांच में कार से मिले शवों की पहचान 42 वर्षीय विकास पुत्र स्वर्गीय घनपत राय

निवासी अंबेडकर कॉलोनी, खेड़ा खुर्द के रूप में हुई है, जो पेशे से ड्राइवर था। उसका शव ड्राइविंग सीट पर मिला। वहीं दूसरा शव 36 वर्षीय बिजेंद्र उर्फ भोला पुत्र दिलबाग निवासी गली नंबर-2, अंबेडकर कॉलोनी, खेड़ा खुर्द का है, जो पेशे से प्लंबर था और कार की पिछली सीट पर मिला। जांच में सामने आया है कि यह कार अंबेडकर कॉलोनी निवासी राकेश कुमार (49) के नाम पर है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है और यहां किराये पर रहता है। स्थानीय पूछताछ और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच में पता चला है कि यह कार सोमवार दोपहर करीब दो बजे से उसी स्थान पर खड़ी थी और उसके बाद कोई भी व्यक्ति कार के अंदर जाता या बाहर निकलता दिखाई नहीं दिया। मौके पर क्राइम टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। पुलिस के अनुसार दोनों शवों पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं। फिलहाल दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में किसी साजिश या आपराधिक पहलू के संकेत नहीं मिले हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।

# राजनीति में विचारों का अचार डालने की कला

पिछले सप्ताह होली और फिर रंगपंचमी पर रंग-पुते चेहरों को देखते हुए मेरे मन में सवाल आया कि क्या हमारी राजनीति भी ऐसी ही रंग-बिरंगी होती जा रही है कि असली चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो जाए! पहले गुलाल और प्राकृतिक रंगों का चलन था तो लोग बड़ी आसानी से पहचान में आ जाते थे, अब पेंट, डामर और गटर के कीचड़ से पुते चेहरे एक जैसे बदरंग लगते हैं, अब आप कहेंगे कि होली तो बीत गई, फिर रंगों की चर्चा क्यों कर रहा हूं? तो कारण निश्चय ही राजनीति है जहां ये मुहावरा बड़ा फिट बैठ रहा है कि विचारधारा तेल लेने गई! चलो विचारों का अचार डालते हैं। 'विचारधारा गई तेल लेने' का मतलब है कि राजनीति में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। कई लोग कहने भी लगे हैं कि जब कोई विचारधारा सत्ता का लक्ष्य न भेद पाए तो फिर मछली की आंख से नजर चुराने में ही भलाई है। वो बात बहुत पुरानी हो गई कि सत्ता मिले न मिले, अपनी विचारधारा पर कायम रहेंगे। ये नया जमाना है, नेताओं ने भी नई राह पकड़ ली है। शिवसेना वाले एक नेताजी से हाल ही में मुलाकात हुई, मैंने पूछा कि पार्टी कैसी चल रही है? उन्होंने खीसें निपोरते हुए कहा कि अरे मैं तो इन दिनों भाजपा में हूं।

एनसीपी के एक नेताजी मिले। मैंने पूछ कि क्या हाल है? कहने लगे कि बहुत अच्छा चल रहा है। भाजपा जैसी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। वो कहने लगे कि हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो अपने मतदाताओं की उम्मीदें कैसे पूरी कर पाएंगे? मेरे पास बैठे पत्रकार ने विचारधारा की बात छेड़ी तो नेताजी कहने लगे कि अरे, विचारों को लिए बैठेंगे तो जवानी संघर्ष में ही बीत जाएगी। विचार का क्या अचार डालेंगे? हमारी बात तो छोड़िए। राहुल जी के खासमखास ही उनका साथ छोड़ गए। इस तरह का जवाब सुनकर अब मैं यह सोच रहा हूं कि क्या हालचाल जानने से पहले ये पूछ लूं कि वह इन दिनों किस पार्टी में है? वैसे इस तरह का सवाल किसी वामपंथी नेता से नहीं पूछ सकते। चीन और रूस ने वामपंथी सोच को त्याग दिया लेकिन हमारे देश के वामपंथी दोस्तों ने अपनी विचारधारा को नकेल कस रखी है कि प्रलोभन में मत पड़ना! वामपंथी हैं, थे और रहेंगे।

आपको याद होगा कि एक समय सभी विपक्षी दल मिलकर ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमत हो गए थे लेकिन वामपंथी नेता प्रकाश करात और हरकिशन सिंह सुरजीत ने वीटो लगा दिया कि विपक्षी दलों से विचारधारा नहीं मिलती, इसलिए ज्योति बाबू पीएम नहीं बनेंगे! हालांकि विचारधारा को लेकर अडिगता के बारे में भाजपा की भी तारीफ करनी होगी कि जब संसद में संख्या केवल 2 थी तब भी भाजपा नेताओं ने विचारधारा नहीं बदली। कोई कैसे भूल सकता है कि कांग्रेस की जब तूती बोलती थी तब राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, मधु दंडवते, मृणाल गोरे जैसे नेता अपने विचारों के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने पाला नहीं बदला। एन.डी. पाटिल की तो याद आपको होगी ही, वे बड़े शेतकरी नेता थे और रिश्ते में शरद पवार के बहनोई होने के बावजूद विचारों को लेकर उनके प्रबल विरोधी थे। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे, मगर अब जमाना बदल गया है। अभी महाराष्ट्र नगरीय निकाय चुनाव के दौरान किसी ने मुझसे बड़ी दिलचस्प बात कही कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है, यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल है, जो मुंबई में हाथ में हाथ डाले खड़ा है, वह पुणे पहुंच कर विरोधी खेमे में खड़ा हो गया। तीसरी जगह किसी तीसरे के साथ खड़ा नजर आया। चुनाव के दौरान जो हुआ वह तो दिमाग का दही बनाने वाला मामला था। बीएमसी का चुनाव तो भाजपा और शिवसेना (शिंदे) ने एक साथ लड़ा। एनसीपी (अजित पवार गुट) सरकार के साथ है लेकिन बीएमसी का चुनाव अलग लड़ा लेकिन ये सारे समीकरण पुणे में बदल गए, वहां भाजपा ने अलग चुनाव लड़ा और शिवसेना शिंदे ने अलग लड़ा। एनसीपी का अजित पवार गुट पुणे में शरद पवार के साथ हो गया! मगर नागपुर में दोनों ने अलग चुनाव लड़ा। मुंबई में कांग्रेस ने ठाकरे बंधुओं से रिश्ता तोड़ लिया था लेकिन पुणे में हाथ मिला लिया। मुंबई में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाली वंचित बहुजन आघाड़ी पुणे में कांग्रेस के खिलाफ लड़ी। राज्य की सत्ता में भागीदार भाजपा, शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजित) ने छत्रपति संभाजी नगर में अलग-अलग किस्मत आजमाई। नासिक में भाजपा अलग थी तो शिंदे और पवार साथ थे। महापौर के लिए भी अजब-गजब गठबंधन हुए। भिवंडी-निजामपुर शहर नगर निगम के महापौर चुनाव में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत था। उसने स्नेहा पाटिल को उम्मीदवार बनाया लेकिन भाजपा के नारायण चौधरी बिफर गए। उन्हें शरद पवार वाली एनसीपी के नेतृत्व वाले भिवंडी सेक्युलर फ्रंट ने समर्थन दे दिया और वे मेयर बन गए। एक भाजपाई का दर्द छलका कि बाहर से आए लोग पार्टी में मजे ले रहे हैं तो हम क्या बस जाजम बिछाने में जिंदगी गुजार दें? चंद्रपुर में कांग्रेस बहुमत के करीब थी लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के समर्थन से भाजपा का महापौर चुना गया। वैसे मौजूदा दौर में कुछ लोग रामदास आठवले की तारीफ करते हैं कि वो सबसे सच्चे नेता हैं। अपने विचारों को लेकर स्पष्ट हैं। वे साफ कहते हैं कि जो सत्ता में है, हम उसके साथ हैं, जिसके साथ हम हैं, वह सत्ता में है! यानी जो दिल में है, वही बोलते हैं। कोई लाग-लपेट नहीं। मगर दूसरे लोगों की हालत ऐसी है कि जो रंग चेहरे पर लगा है, उसे पलक झपकते ही साफ कर लेते हैं और दूसरा लगा लेते हैं। दूसरा हटाते हैं, तीसरा लगा लेते हैं। मतदाताओं को समझा भी देते हैं कि उनकी भलाई के लिए ही उन्होंने खुद को रंग-बिरंगा बना लिया है। जनता जानती है कि उसका काम ताली बजाना है, वह ताली बजाए जा रही है!

# बिहार -नए मुख्यमंत्री के सामने नीतीश से अधिक करके दिखाने की चुनौती

भारतीय राजनीति में पिछले एक दशक से नेताओं के लिए 75वां वर्ष वानप्रस्थ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की राजनीति से अलग होने की इच्छा जताते समय अपनी उम्र का कोई उल्लेख नहीं किया, मगर उम्र का पड़ाव एक ऐसा सच है, जो किसी से छुपा भी नहीं है। वैसे भी नीतीश कुमार राज्यसभा में तो रहेंगे ही और उन्होंने अपने राज्यसभा जाने के फैसले में जो संदेश 'एक्स' पर जारी किया था, उसमें भी उल्लेख है कि उनकी सहयोगी की भूमिका बनी रहेगी। उधर भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह पिछले दिनों यह स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव बीते अभी ठीक से 3 महीने से कुछ ज्यादा ही समय हुआ है। बिहार का विधानसभा चुनाव भाजपा-जद (यू) गठबंधन ने नीतीश के चेहरे पर ही जीता था। हालांकि चुनाव के दौरान कुछ लोग अटकलें लगा रहे थे कि बड़ी जीत के बाद भाजपा मुख्यमंत्री पद का दावा कर सकती थी लेकिन नीतीश के नेतृत्व में चुनाव जीता गया था, इसीलिए वह रिकार्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री भी बने। नीतीश कुमार 2 दशक से ज्यादा समय से बिहार की राजनीति की धुरी माने जा रहे हैं। सीटें कम आईं, ज्यादा आईं, कुर्सी पर वही रहे (अपवादस्वरूप एक बार छोड़ उन्होंने ही जीतन राम मांझी को कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया था।) इसी से उनकी यह छवि मजबूत हुई है कि वह बिहार के धुरी हैं। दलितों में महादलित बनाने के बड़े काम के अलावा कुर्मी-कुशवाहा पिछड़े और महा पिछड़े का संतुलन बनाकर उन्होंने पिछड़ों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी को बिहार की राजनीति के उस कोने में बैठा दिया है, जो विपक्ष का कोना कहलाता है। नीतीश कुमार ने कभी मूल्यों की राजनीति से अपनी पहचान बनाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की राजग सरकार में उन्हें रेलमंत्री बनाया गया था, 1 अगस्त, 1999 को गैसल रेल हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। मार्च 2000 में वाजपेयी सरकार के समर्थन पर समता पार्टी के सदस्य के रूप में वह पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल सिर्फ 7 दिन का था। सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 2005 में उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर बहुमत से सरकार बनाई। उनका यही कार्यकाल बिहार और बिहार की राजनीति को बदलने वाला कहा जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक लाख से अधिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की। कई गांवों में बिजली पहुंचाई, सड़कों का निर्माण किया, महिला निरक्षरता दर आधी कर दी, अपराध पर नकेल कसी, बिहार के लोगों की औसत आय भी तेजी से बढ़ी। अपने पहले पूर्ण कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े काम किए। उन्होंने छात्राओं को साइकिल देने और स्कूल में भोजन कार्यक्रम शुरू किया। इससे बड़ी संख्या में लड़कियों ने स्कूलों में दाखिला लेना शुरू किया और स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी आई। 2010 के चुनाव में पहली बार बिहार में महिला और युवा मतदाताओं की उच्च भागीदारी देखने को भी मिली। यह नीतीश की बढ़ती लोकप्रियता का प्रतीक था। नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन बाबू नाम मिला तो इसके पीछे उनके द्वारा किए गए कार्य ही थे। शराबबंदी ने महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। नीतीश कुमार ने बिहार में जो किया है, उसके बाद अब उनकी जगह लेने वाले मुख्यमंत्री के लिए उससे आगे बढ़कर करने की चुनौती होगी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ढांचागत विकास और गरीबी अब भी बिहार की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है और कृषि आधारित व्यवस्था मौजूदा समय में लाभ का बड़ा सौदा नहीं है। माना जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री भाजपा से होगा। यह मानने के पीछे ठोस वजह है कि भाजपा सबसे बड़ा दल है और इसलिए मुख्यमंत्री उसका होना चाहिए। मगर बिहार में मुख्यमंत्री का पद कांटों का ताज भी है। इसके साथ चुनौतियां भी हैं। यहां सिर्फ दलीय समीकरण ही मायने नहीं रखते, सामाजिक या कहें जातीय समीकरण भी साधने पड़ते हैं। नीतीश ने जातीय समीकरण बड़े सलीके से साधे थे और जो वर्ग या जाति उनके साथ नहीं थी, वह भाजपा के साथ थी। अल्पसंख्यकों का एक वर्ग भी उनके साथ था। सीमेंट मजबूत था।

लेकिन अब भाजपा के नेतृत्व में चीजें आने से समीकरणों की रिसैटिंग होगी ही। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो दिख रही है, वह है पिछड़ों के अलावा अति पिछड़े और दलितों को साधे रखना। यूं तो ये वर्ग या तो जद (यू) के साथ हैं या फिर भाजपा के साथ लेकिन भाजपा के नेतृत्व में आते ही इन समीकरणों को पुख्ता करना नए मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी होगी। बिहार की राजनीति के मद्देनजर यह तय है कि मुख्यमंत्री पिछड़े/अति पिछड़े वर्ग का ही होगा। लेकिन सबको साधना आसान काम नहीं होगा। यह जरूर है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद बहुत दिन बाद उसका मूल वोटर, जिसमें पिछड़ों का एक वर्ग और सवर्ण वोट है, उसकी बांछें खिल सकती हैं। लेकिन सबको लेकर चलना आसान नहीं होगा, खास तौर से जब जातीय हित भी टकराते हैं। वैसे नए मुख्यमंत्री के सामने शासन में कायाकल्प की चुनौती भी होगी, क्योंकि उसे कुछ नया कर दिखाना होगा, नीति के तौर पर भी और सामने दिखने के तौर पर भी।

## सम्पादकीय...

### सऊदी अरब की मदद के लिए रणभूमि में उतर सकता है पाकिस्तान, युद्ध का दायरा और फैलेगा!

पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते सुरक्षा हालात के बीच पाकिस्तान एक बेहद जटिल सामरिक दुविधा में फंस गया है। सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने इस्लामाबाद के सामने यह कठिन सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वह अपने पुराने सहयोगी सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा या फिर क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के सऊदी दौरे ने इस बहस को और तेज कर दिया है। दरअसल ईरान द्वारा सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाओं के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए सामरिक रक्षा समझौते की परीक्षा शुरू हो गयी है। इस समझौते के अनुसार यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी सुरक्षा में सहयोग करेगा। इस संकट के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने रियाद में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। इस बैठक में ईरानी हमलों और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात पर चर्चा की गयी। दोनों देशों ने साझा रक्षा समझौते के तहत संभावित कदमों पर विचार किया। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यदि पाकिस्तान सऊदी अरब का सैन्य समर्थन करता है तो वह सीधे ईरान के साथ टकराव की स्थिति में आ सकता है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पहले से ही अस्थिर है और ऐसे में नया संघर्ष उसके लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। मगर यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब का घनिष्ठ सहयोगी रहा है। सऊदी अरब ने आर्थिक सहायता और तेल आपूर्ति के माध्यम से कई बार पाकिस्तान की मदद की है। दूसरी ओर पाकिस्तान की ईरान के साथ लंबी सीमा लगती है और इन दोनों देशों के बीच भी सुरक्षा और ऊर्जा से जुड़े कई हित हैं। यही कारण है कि अब तक पाकिस्तान ने इस संघर्ष में सीधे शामिल होने से बचने की कोशिश की है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस्लामाबाद खुलकर सऊदी अरब के पक्ष में उतरता है तो इससे ईरान के साथ संबंध गंभीर रूप से बिगड़ सकते हैं और सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। हम आपको बता दें कि इस संकट का एक महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति भी है। देश में सुन्नी और शिया समुदाय दोनों की बड़ी आबादी है। ईरान शिया बहुल देश है जबकि सऊदी अरब सुन्नी नेतृत्व वाला राष्ट्र है। ऐसे में यदि पाकिस्तान किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करता है तो देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका भी होगी। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किये थे और गुस्साई भीड़ ने पाकिस्तान स्थित अमेरिकी मिशन पर हमला भी बोल दिया था। इसके बाद हालात काबू करने के लिये सुरक्षा बलों को कार्रवाई करनी पड़ी थी जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आयीं। इस घटना ने इस्लामाबाद की चिंता और बढ़ा दी है। पाकिस्तान की सरकार को आशंका है कि यदि वह खुलकर ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के समर्थन में सेना उतारता है तो देश में मौजूद शिया समुदाय भड़क सकता है और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी कारण पाकिस्तान की सरकार और सेना अब तक संतुलित नीति अपनाने की कोशिश करती रही है।

# फिर हिन्दी-चीनी भाई-भाई!

> चीन और भारत अब प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सहभागी है। अगर दोनों देश साथ-साथ चले तो आने वाली सदी इन दोनों देशों की होगी। चीन के बदलते रवैये के तार मिडिल ईस्ट संघर्ष से भी जुड़े हुए हैं। तेल और ऊर्जा संकट सामने खड़ा है। अमेरिकी दबाव का मुकाबला करने के लिए चीन अब भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहता है। भारत, रूस और चीन त्रिकोण की अवधारणा भी कोई नहीं है। अगर तीनों शक्तियां एक साथ आ जाए तो दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित हो सकता है। तब अमेरिका किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत-चीन महत्वपूर्ण पड़ोसी और ग्लोबल साऊथ के सदस्य होने के नाते दोनों के बीच सभ्यतागत संबंध है। ग्लोबल साऊथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है और यह मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमेरिका में स्थित है।

भारत और चीन दो पड़ोसी देश हैं। दोनों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सीमाएं मिली हुई हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद से एक ही समय संघर्ष, आपस में असीम सद्भाव, करीब-करीब एक ही समय आजादी, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1949 में चीन। कभी ऐसा भी समय आया कि पंचशील के 'नाद' से दोनों देश गूंजते थे। कभी वह समय था जब हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे को गीतों की शक्ल में गाया गया। चीन भगवान बुद्ध को मानने वाला देश और भारत भगवान बुद्ध को दसवें अवतार की संज्ञा देने वाला देश। हजारों वर्ष के इतिहास में कभी भी वैर या वैमनस्य का कोई भी उदाहरण नहीं रहा। दोनों देश विश्व के सबसे बड़े बाजार हैं लेकिन 1962 में चीन के भारत पर हमले ने ऐसी अविश्वास की खाई पैदा की जो आज तक पाटी नहीं जा सकी। दोनों देशों के संबंधों पर आज भी 1962 युद्ध की छाया साफ दिखाई देती है। भारत और चीन के संबंधों में बहुत उथल-पुथल रही है। सीमाओं पर काफी टकराव रहा है। चीन की विस्तारवादी नीतियां संबंधों में आड़े आती रहीं। 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के हजारों सैनिक और भारी हथियार तैनात कर दिए गए। 2024 के अंत तक सीमाओं से दोनों देशों के सैनिकों की वापसी की खबरें आईं और उसके बाद दोनों देशों के संबंधों पर जमी बर्फ पिघल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभालने की जिस तरह से एक तरफा दादागिरी दिखानी शुरू की उसके बाद भारत और चीन के संबंधों में नरमी आई। सीमा पर लंबे समय के गतिरोध के बाद भारत और चीन के तनाव कम करने और बातचीत की ओर कदम बढ़ाए। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और सीमा पर स्थिरता बनाए रखने पर सहमति बनी। ट्रंप की नीतियों ने भारत और चीन दोनों को निशाना बनाया। जिसके चलते दोनों एशियाई शक्तियों को साझा, आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों पर एक साथ आने का मौका दे दिया है। हर वक्त चौधराहट दिखाने वाला चीन फिर से हिन्दी-चीन भाई-भाई वाली बात करने लगा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत और चीन से सुधरते रिश्तों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के बजाय साझेदार और खतरे के बजाय अवसर के रूप में देखना चाहिए। वांग यी का कहना है कि चीन और भारत महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं और दोनों ग्लोबल साउथ के सदस्य होने के नाते गहरे सांस्कृतिक संबंध तथा व्यापक साझा हित रखते हैं। उन्होंने ये बयान बीजिंग में आयोजित 14वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सत्र के दौरान एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में दिया है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं और दोनों ही वैश्विक दक्षिण के हिस्से हैं, जिनके बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और व्यापक साझा हित हैं। चीन-भारत के बीच आपसी विश्वास और सहयोग साझा विकास के लिए बहुत फायदेमंद है जबकि विभाजन और टकराव एशिया के पुनरुत्थान में सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के रिश्ते अब सामान्य पटरी पर लौट आए हैं। इसलिए दोनों देश आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन को इस साल और अगले साल ब्रिक्स की बारी-बारी से अध्यक्षता करने में एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए। भारत इस साल अध्यक्ष है और अगले साल ये जिम्मेदारी चीन के पास होगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से ठोस सहयोग बढ़ाकर ग्लोबल साउथ के देशों को नई उम्मीद दी जा सकती है। दोनों देशों को एक-दूसरे की ओर कदम बढ़ाते हुए बाधाओं को दूर करना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका बीते कुछ सालों से लगातार चीन को आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर घेरने की कोशिश कर रहा है। पहले अमेरिका ने चीन के सबसे ज्यादा निवेश वाले वेनेजुएला में हमला कर उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया तो अब ईरान पर हमला कर चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। ऐसे में चीन अपने पड़ोसी देश भारत और रूस को अपने खेमे में बनाए रखने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है जिससे कि वह रणनीतिक रूप से अमेरिका के आगे कमजोर न पड़े। यही कारण है कि अब वो भारत के साथ दोस्ती और भाईचारे की दलील दे रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने कोई नई बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणव मुखर्जी की 2006 में चीन यात्रा के दौरान दिए गए वक्तव्य को ही दोहराया है। तब प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि भारत 1962 वाला भारत नहीं है। अब भारत बहुत विकास कर चुका है। चीन और भारत अब प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सहभागी है। अगर दोनों देश साथ-साथ चले तो आने वाली सदी इन दोनों देशों की होगी। चीन के बदलते रवैये के तार मिडिल ईस्ट संघर्ष से भी जुड़े हुए हैं। तेल और ऊर्जा संकट सामने खड़ा है। अमेरिकी दबाव का मुकाबला करने के लिए चीन अब भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहता है। भारत, रूस और चीन त्रिकोण की अवधारणा भी कोई नहीं है। अगर तीनों शक्तियां एक साथ आ जाए तो दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित हो सकता है। तब अमेरिका किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत-चीन महत्वपूर्ण पड़ोसी और ग्लोबल साऊथ के सदस्य होने के नाते दोनों के बीच सभ्यतागत संबंध है। ग्लोबल साऊथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है और यह मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमेरिका में स्थित है। दुनिया की अग्रणी, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण मूल सदस्य हैं लेकिन बाद में सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान को शामिल कर इसके सदस्य देशों का विस्तार किया गया है। अमेरिका कभी भी हमारा विश्वसनीय मित्र नहीं बना है। भारत-अमेरिका संबंधों को एक टैक्टिकल यानि रणनीतिक ही कहा जा सकता है।

वह चीन और रूस के खिलाफ भारत के कंधे पर बंदूक रखकर अपना मकसद हल करना चाहता है। राजधानी दिल्ली में जब एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने यह कहा था कि अमेरिका भारत के साथ वह गलती नहीं दोहराएगा जो उसने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। इसका अर्थ यह था कि अमेरिका भारत के बाजारों को विकसित नहीं होने देगा ताकि भारत व्यापार में हमें पीछे न छोड़ दें। भारत के आर्थिक विकास को रोकने के लिए अमेरिका का रवैया नग्न हो चुका है।

तब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका पर तंज कसा कि भारत का उत्थान कैसे होगा, यह भारत ही तय करेगा। यह हमारी ताकत से तय होगा न कि दूसरों की गलतियों से। सवाल भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का भी है कि वह अपने हितों को देखते हुए किस देश के साथ संबंधों का विस्तार करे और किस से दूरी बनाए। तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन के रुख में लगातार नरमी आई है। उम्मीद है कि बदलती भू-राजनीतिक स्थितियों में दोनों देश अच्छे मित्र बनकर आगे बढ़ेंगे।

# मौसम का बदलता मिजाज खतरे का संकेत

भारत में ग्लोबल वार्मिंग का असर अब साफ नजर आने लगा है। अभी मार्च माह की शुरुआत ही हुई है और गर्मी ने अभी से ही अपने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार मार्च के महीने में ही पसीने छूटने की मुख्य वजह तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी है। मौसम के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यह तापमान इस समय के लिए सामान्य से अधिक माना जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी तेज गर्मी मार्च के शुरुआती दिनों में कम ही देखने को मिलती है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि पिछले कई दशकों में मार्च के दौरान इतनी गर्मी कम ही दर्ज की गई है। कई लोग इसे पिछले करीब 50 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म मार्च की शुरुआत में से एक मान रहे हैं। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन का असर मौसम पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी वजह से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और गर्मी पहले की तुलना में जल्दी शुरू हो रही है। इसका असर यह है कि अब तापमान तेजी से बढ़ रहा है और गर्म दिनों की संख्या भी बढ़ रही है। कभी-कभी लू की अवधि भी पहले से अधिक लंबी हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के कई शहरों ने गर्मी के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ स्थानों पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो आने वाले वर्षों में गर्मी और भी तीव्र हो सकती है। भारत की पारंपरिक पहचान उसके विविध ऋतु-चक्र से रही है, लेकिन अब यह चक्र पूरी तरह से टूट चुका है। ''सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट'' (सीएसई) एवं ''डाउन टू अर्थ'' की नई रिपोर्ट'' इंडिया क्लाइमेट 2025'' ने एक डरावनी तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां ''चरम मौसम'' कोई अपवाद नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत बन गया है। सीएसई ने मौसम विभाग, गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग एवं विभिन्न राज्यों की एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषण किया है। साथ ही साल 2022 से सितंबर 2025 तक लगभग 1500 दिनों की भारत की मौसम संबंधी आपदाओं का एक नया नक्शा तैयार किया है। अध्ययन का सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष यह है कि भारत में ऋतुओं का आपस में विलय हो रहा है। सर्दी, गर्मी और वर्षा के बीच की स्पष्ट रेखाएं अब धुंधली पड़ चुकी हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 के पहले नौ महीनों (जनवरी से सितंबर) के दौरान देश ने लगभग 99 प्रतिशत दिन चरम मौसम की मार झेली है। इसका मतलब है कि इन 273 दिनों में से शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो, जब भारत के किसी न किसी हिस्से में भारी वर्षा, लू, ओलावृष्टि या चक्रवात जैसी आपदा न आई हो। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है।

तीन साल बाद मार्च के पहले सप्ताह में ही तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस महीने तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। 2025 में, मार्च के पहले सप्ताह के दौरान, उत्तर प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि रात का तापमान लगभग 14 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 मार्च 2026 को दिन का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो पिछले तीन वर्षों में मार्च की शुरुआत का उच्चतम तापमान है। इससे पहले 2023 में 1 मार्च को दर्ज किया गया अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, मार्च की शुरुआत में इतना अधिक तापमान इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ सकती है। जाहिर है मौसम के मिजाज में आ रहे इस असामान्य बदलाव का हमारे जीवन और आजीविका पर गहरा प्रभाव आने वाले दिनों में नजर आएगा, जिसको लेकर देशव्यापी चर्चा जारी है। विशेषकर उत्तर भारत के कृषि क्षेत्र में इसके नकारात्मक आर्थिक परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। वास्तव में मौसमी बदलाव फलों के नाजुक जैविक चक्र को बाधित कर रहा है, जिसके चलते उपज में भारी नुकसान के साथ-साथ गुणवत्ता में गिरावट की आशंका व्यक्त की जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मार्च का महीना किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

तापमान में वृद्धि से रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं पर असर पड़ेगा। गर्मी के कारण अनाज का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा जिससे पैदावार कम होगी। गर्म हवाओं से सरसों, चना और मटर जैसी फसलों को नुकसान हो सकता है। बढ़ते तापमान के कारण खेतों की मिट्टी जल्दी सूख जाती है। इससे सिंचाई की लागत बढ़ जाती है और फसलों पर दबाव पड़ता है। चिंता की बात यह भी है कि हिमाचल प्रदेश के सेब के बागों में कम होती ठंडक से उत्पादकता में गिरावट देखी जा रही है। इससे बचने के लिए अनुकूलन उपायों में जलवायु अनुरूप बागवानी पद्धतियों को अपनाने और दीर्घकाल में सेब पट्टी को ऊंचे क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की जरूरत होगी। आवश्यकता होगी कि हम सूखा-सहिष्णु फसलों को अपनाएं। कम जल के बेहतर उपयोग के प्रयास हों। मौसम के बदलने के दौरान बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है जिससे उन्हें श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा अधिक हो जाता है। सुबह-शाम की ठंडी हवा, धूल-मिट्टी और प्रदूषण भी बच्चों में एलर्जी और अस्थमा की समस्या को बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों को लेकर इस मौसम में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक देने से परहेज करें, उन्हें धूल और धुएं से बचाकर रखें। इसके साथ ही बच्चों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाना भी जरूरी है। कई स्टडी के द्वारा यह साफ हुआ है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले लू के दिनों की संख्या 1980 के बाद से दोगुनी से भी अधिक हो गई है। हमारे देश में तीव्र शहरीकरण, सघन निर्माण और हरित क्षेत्रों के लगातार जारी क्षरण के चलते भी तापमान में वृद्धि हुई है।

ऐसे में बढ़ते तापमान से उत्पन्न जल व ऊर्जा संकट से निपटने के लिए तत्काल कारगर योजनाओं की जरूरत है। इसके साथ ही शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में तेजी से होने वाले परिवर्तन के इस नये असामान्य परिदृश्य के लिए नागरिकों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के लिए भी एक नया चार्टर बनाने की आवश्यकता होगी। सरकारों की तैयारियों को लेकर भी स्पष्ट रीति-नीति का निर्धारण जरूरी है। निस्संदेह, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के निस्तारण के लिए रणनीतियों को लेकर सहभागी दृष्टिकोण प्रभावकारी हो सकता है। आने वाले समय में मौसम की चरम स्थितियां घातक साबित हो सकती हैं, जिनका मुकाबला मौजूदा अपर्याप्त प्रशासनिक योजनाओं के जरिये संभव न होगा। इसके लिए कारगर रणनीतियां बनाने की जरूरत होगी। हमें बिजली की अनुमानित मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करना होगा। समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी करने तथा प्रभावी उपचार की उपलब्धता भी जरूरी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमें बिजली और पानी की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। वहीं आने वाले वर्षों में मौसम चक्र में आने वाला यह बदलाव और तेज होने का अनुमान है। अगर समय रहते उससे बचाव के उपाय नहीं किए गए तो खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने करना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पंचशीला एन्क्ले., दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया संपादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/40862)

# अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वछता व महिला सशक्तिकरण का संदेश, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित

कसया, कुशीनगर ।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को नगर पालिका परिषद कुशीनगर के सौजन्य से सिटियानो डी सॉल्यूलशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम नगर पालिका परिषद पडरौना में आयोजित किया गया, जिसमें स्वछता को बढ़ावा देने और समाज में प्रेरणादायक कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद कुशीनगर की अध्यक्ष किरण राकेश जायसवाल के प्रतिनिधि राकेश जायसवाल तथा अधिशासी अधिकारी अंकिता शुक्ला मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वछ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत स्वछता के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित कर उनके कार्यों की सराहना की गई। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के विकास की आधारशिला है और जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन स्वतः दिखाई देता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल ने कहा कि स्वछ भारत मिशन प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसका उद्देश्य स्वछ और स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वछता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखें। वहीं अधिशासी अधिकारी अंकिता शुक्ला ने कहा कि नगर पालिका परिषद द्वारा समय-समय पर स्वछता और जनजागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज में परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उनके प्रयासों से स्वछता अभियान को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने सिटियानो डी सॉल्यूलशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए जा रहे स्वछता संबंधी कार्यों की भी सराहना की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को स्वछता के प्रति जागरूक किया गया तथा शहर को स्वछ और सुंदर बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई। अंत में सभी ने मिलकर स्वछता बनाए रखने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

## रेलवे प्रशासन द्वारा ढाला समपार को बंद किये जाने को लेकर नगरवासियों ने दिया एस डी एम को ज्ञापन

कप्तानगंज(कुशीनगर)।

सहायक मंडल इंजीनियर पूर्व गोरखपुर द्वारा जनहित के विरूद्ध आदेश कि कप्तानगंज रेलवे स्टेशन यार्ड स्थित समपार स.17 किलो 356/16 को स्थाई रूप से बंद किये जाने को लेकर मंगलवार को नगर के व्यापारी विद्यालय प्रबंधतंत्र, समाजसेवी व विभिन्न राजनैतिक दल के नेताओं ने एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी विनोद कुमार गुप्ता को सौप कर इस महत्वपूर्ण ढाले /समपार को तब तक न बंद किया जाय कि जब तक वहां अंडर ग्राउंड पास न बन जाय की मांग किया। बताते चलें कि इस समपार ढाले से तकरीबन हजारों की संख्या में विभिन्न गांव के व्यापारी साइकिल से व अन्य साधनों से व छात्र , मरीजों का आना जाना होता है।

ऐसे में अगर यह ढाला बंद होता है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में जनहित में इस ढाले को बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को मानें तो रेलवे प्रशासन जिले के समस्त अधिकारियों को 11 मार्च को उस समपार पर सुरक्षा हेतु पहुंच कर समपार को बंद करने में मदद करने की अपील किया है। जैसे यह खबर स्थानीय लोगों को लगी तो जनाक्रोश भड़क उठा।

व्यापारी ,नेता किसान विद्यालय तंत्र सब सड़क पर आ गए और रेलवे के इस जनहित के मुद्दे के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिए।लोगों ने एक बैठक कर निर्णय लिया कि किसी कीमत पर यह समपार बंद नहीं होने देंगे। इसके अलावा इस संदर्भ में एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी कप्तानगंज, रेलवे स्टेशन अधीक्षक, थानाध्यक्ष कप्तानगंज को देने पर विचार हुआ।

इसके बाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश अग्रहरि के नेतृत्व में सैकड़ों लोग तहसील पहुंच कर समपार को न बंद किये जाने का ज्ञापन सौंपा। एस डी एम विनोद गुप्ता ने लोगों को आश्वस्त किया और इस ज्ञापन को सम्बंधित अधिकारियों तक पहुंचाने को कहा।

## अंतर्रायीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, पिकअप, जनरेटर व दो मोटरसाइकिल के साथ तीन शातिर गिरफ्तार

कुशीनगर। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कसया और थाना तुर्कपट्टी की संयुक्त पुलिस टीम ने अंतर्रायीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की एक पिकअप, एक जनरेटर तथा दो मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर केशव कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कसया कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में सुलेमान राईनी निवासी रामधाम जंगल विशुनपुरा थाना कोतवाली पडरौना, शशिरंजन तिवारी निवासी बेलाव थाना दरौली जिला सिवान (बिहार) तथा शिवम उर्फ शुभम उर्फ शिवकुमार निवासी राम गुलाम टोला थाना कोतवाली देवरिया, हाल मुकाम बाबू बाजार फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर शामिल हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे संगठित गिरोह बनाकर विभिन्न स्थानों पर मोटरसाइकिल व चार पहिया वाहनों की रेकी करते थे। मौका मिलने पर वाहन चोरी कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा कर लेते थे और बाद में बिहार ले जाकर स्थानीय खरीदारों को बेच देते थे। इस तरह वे अंतर्रायीय स्तर पर वाहन चोरी का नेटवर्क चला रहे थे।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक पिकअप वाहन, एक जनरेटर, एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामदगी के आधार पर विभिन्न थानों में दर्ज कई मुकदमों का खुलासा हुआ है। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में चौकी प्रभारी कस्बा कसया उपनिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक दीपक प्रधान, उपनिरीक्षक आदर्श मिश्रा, कांस्टेबल आशुतोष सिंह, अजय चौहान, अभिषेक यादव, रामबचन बिन्द, उमाशंकर यादव के साथ थाना तुर्कपट्टी के उपनिरीक्षक कैलाश यादव, चंदन प्रजापति, राहुल कुमार तथा कांस्टेबल धीरेन्द्र प्रताप सिंह व शिव प्रकाश शामिल रहे।

## जिला कारागार का औचक निरीक्षण, बंदियों की सुविधाओं और रिहाई मामलों की हुई पड़ताल

देवरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धनेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में सचिव एवं सिविल जज (सीडी) शैलजा मिश्रा ने जेल परिसर का निरीक्षण कर बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कारागार की पाकशाला का जायजा लिया और भोजन व्यवस्था की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि बंदियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद उन्होंने कारागार चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया और वहां मौजूद बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं। इस दौरान संबंधित मामलों के समाधान के लिए जेल अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए गए। सचिव ने ऐसे बंदियों के मामलों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा, जिनकी जमानत न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन जमानतदार के अभाव में वे अभी भी जेल में निरुद्ध हैं। उन्होंने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों की सूची तैयार कर आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। निरीक्षण के दौरान वृद्ध बंदियों, गंभीर रूप से बीमार कैदियों और महिला बैरक में रह रही महिलाओं के साथ मौजूद बच्चों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। सचिव ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर इन सभी को तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनके स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। निरीक्षण के समय जिला कारागार अधीक्षक आशीष रंजन, कारापाल राजकुमार वर्मा तथा जेल वार्डन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

## करंजाकला ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संगोष्ठी व उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित, बचों ने दी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति

जौनपुर।

ब्लॉक संसाधन केंद्र करंजाकला में मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य, प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्षों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि करंजाकला सुनील यादव (मम्मन) ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों की प्रगति और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और ग्राम पंचायतों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने निपुण भारत मिशन और समग्र शिक्षा अभियान के तहत चल रहे प्रयासों की सराहना करते हुए सभी से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देने की अपील की। विशिष्ट अतिथि डॉ. गोरखनाथ पटेल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उन्होंने कहा कि निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों को बुनियादी साक्षरता और गणितीय दक्षता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों और समाज की सहभागिता भी जरूरी है। इस अवसर पर राम कृष्ण यादव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) करंजाकला ने भी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में श्रवण कुमार यादव (खंड शिक्षा अधिकारी करंजाकला) सहित शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। करंजाकला क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों ने अपनी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय आविष्कार प्रतियोगिता में सफल बच्चों को मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। साथ ही ब्लॉक के दूरस्थ विद्यालयों से आए बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी उन्हें सम्मानित किया गया।

# उत्तम नगर हत्याकांड : वीरान गलियां, बाजारों में सन्नाटा, छह दिन बाद भी दहशत, मुख्य आरोपी सायरा समेत आठ पकड़े

नई दिल्ली । उत्तम नगर के ए-ब्लॉक की जिन तंग गलियों में कभी बच्चों का शोर-शराबा और बाजारों को रौनक हुआ करती थी, वहां की गलियां अब वीरान हो गई हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा है। होली हत्याकांड के बाद से स्थानीय लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई है। स्थानीय लोगों के मन में दहशत का माहौल बना हुआ है। वारदात के छह दिन बीत जाने के बाद भी जनजीवन पटरी पर नहीं लौट सका है। इलाके में प्रमुख मार्गों की घेराबंदी की गई है। पुलिस की चहल कदमी बढ़ गई है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है। पुलिसकर्मी हालात सामान्य करने में लगे हुए हैं। एहतियात के तौर पर इलाके में केवल परचून और दवा की दुकानें खुली हुई हैं, ताकि जरूरी सेवाओं में बाधा न आए। दुकानदार रोहित ने बताया कि इलाके में ऐसे हालात देखकर लॉकडाउन वाले दिन याद आ गए हैं। तनाव का सीधा असर कारोबार पर पड़ा है। दुकानों के शटर गिरे हैं। लोगों की आवाजाही पर सख्ती बरती जा रही है। निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि पहले पार्क शाम के समय युवाओं और बच्चों की भीड़ से गुलजार रहते थे, लेकिन पार्क के गेट पर ताले लटके हुए हैं। पार्क खुले होने से लोग आकर बैठते थे। टहलते थे और कसरत करते थे, लेकिन अब लोग घरों के अंदर ही बैठे रहते हैं। निवासी अमित ने बताया कि बुलडोजर कार्रवाई के बाद से ही पूरा इलाका संवेदनशील हो गया है। प्रशासन की ओर से एक मकान को ढहाने की कार्रवाई ने इलाके की छवनी में तब्दील कर दिया है। वहीं, सोमवार को स्थिति तब और गंभीर हो गई जब कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुरक्षा कारणों से बैरिकेड्स पर ही रोक दिया। उत्तम नगर इलाके में होली के दिन हुई तरुण की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला 40 साल की सायरा उर्फ काली समेत आठ लोगों को पकड़ लिया है। जिसमें तीन महिला और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने तीनों महिलाओं को खयाला इलाके से पकड़ा है। सायरा वही महिला है, जिसने नए सी बात को बखेड़ा बनाया और बात हत्या तक पहुंच गई। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 40 साल की सायरा उर्फ काली, 50 साल की सरीफन, 36 साल की सलमा, 21 साल का सुहैल उर्फ साहिल, 20 साल के समीर चौहान, 22 साल के फिरोज और 50 साल के इस्माइल (50) के रूप में हुई है। वहीं नाबालिग 14 साल का है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं वारदात में शामिल दो नाबालिगों को पकड़ा है। पुलिस अन्य आरोपियों की जानकारी जुटा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई महिलाओं से पूछतछ कर रही है। इस मामले में और भी लोगों के पकड़े जाने की संभावना है। दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड में पहले ही एक नाबालिग समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

यह घटना होली के दिन उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में हुई। पीड़ित पक्ष का दावा है कि 11 साल की बच्ची अपनी छत से होली खेल रही थी। इसी दौरान अपने ताऊ की ओर फेंका गया एक गुब्बारा नीचे गिर कर फट गया और वहां गुजर रहे मुस्लिम महिला सायरा उर्फ काली पर रंग के छींटें चली गईं। बच्ची के परिवार ने बताया कि उन्होंने महिला से तुरंत माफी मांग ली थी। इसके बावजूद महिला ने हंगामा किया और उसके परिजन और रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। आरोपी परिवार ने मारपीट की। दोस्तों के साथ होली खेलने गया 26 साल का तरुण कुमार इस घटना से अंजान था।

जब वह होली खेलकर घर लौट रहा था तभी आरोपियों ने उसे गली में घेर लिया। उस पर क्रिकेट बैट, लाठियों और पत्थरों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

तरुण कुमार को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अगले दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तरुण की मौत के बाद शुक्रवार को इलाके में काफी तनाव बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने घटना का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों को जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। आरोपी परिवार के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और कुछ वाहनों पर तोड़फोड़ व आगजनी की। तनाव को देखते हुए इलाके को छवनी में तब्दील कर दिया गया है।

# स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

## गोगोई बोले- राहुल को 20 बार टोका गया; रिजिजू का जवाब- प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाते तो अच्छा होता

नई दिल्ली ।

- किरेन रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने पर सवाल उठाए और उन्हें गंभीर नहीं माना.
- रिजिजू ने कहा कि विपक्ष में कंफ्यूजन है और अविश्वास प्रस्तावों के बीच कोई स्पष्ट रणनीति नहीं दिख रही है.
- प्रियंका ने बताया कि 12 वर्षों में केवल नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के सामने सिर नहीं झुकाया है.

लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा चल रही है।

विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोक-टोका गया। उन्हें बार बार रूलिंग बुक दिखाई गई। उन्होंने अपनी स्पीच में एक आर्टिकल का हवाला दिया। इस पर उन्हें मना किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत में बैन किताबें सदन में दिखाईं। उनसे कुछ नहीं कहा गया। इस तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं है।

**गोगोई ने बिरला पर भेदभाव के 3 आरोप लगाए**

2 फरवरी को नेता विपक्ष राहुल गांधी जब बोल रहे थे, तब उन्हें बार-बार रोका गया। स्पीकर सर ने उनके तर्क पर सबूत देने का कहा। 9 फरवरी को शशि थरूर जब बोल रहे थे, तब उनका माइक बंद कर दिया गया। सरकार ने कहा कि बोलिए, लेकिन हम कैसे बोल सकते है जब माइक ऑफ किया गया हो। संसद में ऐसी नई-नई चीजें हो रही है। आज महिला सांसदों के उद्देश्य पर सवाल उठाए जा रहे है। ओम बिरला जी ने पीएम मोदी के समक्ष कहा था कि महिला सांसदों ने पीएम की चेयर घेर ली है। उनके साथ कुछ भी हो सकता था। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बिरला ने किस आधार पर महिला सांसदों पर ये आरोप लगाए।

**रिजिजू ने कहा- जब सेशन चलता है तो राहुल विदेश चले जाते हैं**

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- इन लोगों ने पहले आरोप लगाया कि रूलबुक को बोलने नहीं दिया जाता है। मैं कहता हूं 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष केवल 2 बार बोले। जब सेशन चलता है, तो विदेश चले जाते है। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात बोल के सदन से भाग जाते है। किसी और की बात नहीं सुनते है। फिर कहते है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा कि नेता प्रतिपक्ष पीएम को गले लगा रहा है। अपनी सीट पर बैठकर अपने सांसद को आंख मारता है। जैसा लीडर है तो बाकी के सांसद भी वैसे ही होंगे। मेंबर चेयर को यार कहते है। फिर कहते है कि इसमें गलत क्या है (वेणुगोपाल ने चेयर को यार कहा था। प्रियंका को एलओपी बनाते तो कुछ अच्छा होता। देखिए प्रियंका हंस रही है। जो अच्छा व्यवहार करे तो उसकी सराहना करनी चाहिए। विपक्ष ने हंगामा किया। रिजिजू बोले- मैंने अच्छा बोला है। कांग्रेस क्यों नाराज हो रही है।

**प्रियंका ने कहा- राहुल की सचाई इनसे पचती ही नहीं है**

प्रियंका गांधी ने कहा कि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं। वह नेता प्रतिपक्ष है। और वो नेता प्रतिपक्ष इस सदन में खड़े होके इनके सामने सच बोल देते है। सचाई वो जो बोलते हैं वह इनसे पचती नहीं है।

# एलपीजी संकट के बीच एक्शन मोड में पीएम, संसद भवन में हरदीप पुरी से की मुलाकात

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक की, जिसमें एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा की गई और ईरान के साथ चल रहे युद्ध से उत्पन्न होने वाली संभावित बाधाओं का आकलन किया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच, केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू ईंधन बाजार को संभावित व्यवधानों से बचाने के लिए अध्यादेश वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट) लागू किया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि एक नियंत्रण आदेश जारी किया गया है जिसमें रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) उत्पादन बढ़ाने और देश भर में खाना पकाने की गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख लाइट्रोकार्बन धाराओं को एलपीजी पूल में डालने का निर्देश दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड ने कहा कि वैश्विक ईंधन आपूर्ति को प्रभावित करने वाली वर्तमान भू-राजनीतिक बाधाओं को देखते हुए, एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं तथा अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक गैर-घरेलू क्षेत्रों के लिए इसकी उपलब्धता को प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाए गए हैं। अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति द्वारा की जाएगी और योग्यता, आवश्यकता और उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से कुछ दिनों के लिए व्यावसायिक सिलेंडरों पर प्रतिबंध लगाने का दिशानिर्देश जारी किया गया है। 21 से 25 दिनों के बीच सिलेंडर बुकिंग के संबंध में भी एक सलाह जारी की गई है। उन्होंने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आज शाम सभी तेल कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है। उन्होंने आगे कहा कि राय सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित आंकड़े मांगे है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लिखे पत्र में कहा गया है कि अधिकारी, मुख्यमंत्री और मंत्री हरियाणा में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। राय के सभी उपायुक्तों और डीएफसी को गैस सिलेंडरों से संबंधित दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान होटल एसोसिएशन फेडरेशन के गजेंद्र लूनीवाल ने कहा कि होटल मालिकों में तनाव बढ़ रहा है और सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। सिलेंडर न मिलने पर होटल और रेस्तरां ठप्प हो जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में होटल मालिक अपना खर्च कैसे चला पाएंगे।

# 'बराबरी का एक रास्ता यूसीसी भी'

## मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार की अर्जी पर बोला सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि अगर पूरे देश में सभी महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार अधिकार सुनिश्चित करने हैं, तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे व्यापक विधायी उपाय पर विचार किया जा सकता है.

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर संपत्ति में हिस्सेदारी देने की मांग उठाई गई है. मुस्लिम महिलाओं के बराबर विरासत अधिकार पर सुनवाई के दौरान अदालत ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश की सभी महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने का एक तरीका समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करना भी हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि अगर पूरे देश में सभी महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार अधिकार सुनिश्चित करने है, तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे व्यापक विधायी उपाय पर विचार किया जा सकता है. हालांकि अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यह नीतिगत और विधायी क्षेत्र का मुद्दा है, जिस पर अंतिम निर्णय विधायिका और सरकार को लेना होता है. यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई जिसमें मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर संपत्ति में हिस्सेदारी देने की मांग उठाई गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर विरासत अधिकार नहीं देते. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या अदालत पर्सनल लॉ की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकती है? जस्टिस बागची ने एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि इस फैसले में माना गया था कि पर्सनल लॉ को संविधान की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता.

# ईरान के लिए आज कयामत की रात, अमेरिका के रक्षा मंत्री की चेतावनी- आसमान से होगी बारूद की बारिश

वाशिंगटन । अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार का दिन ईरान के अंदर अमेरिकी हमलों का अब तक का सबसे भीषण दिन होगा। यह चेतावनी तब आई है जब ईरान की हमला करने की ताकत कम होती दिख रही है, लेकिन उसने लड़ाई जारी रखने का संकल्प है। दूसरी तरफ, इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, हम उनकी हड्डियां तोड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ किया कि इस युद्ध का मकसद ईरान की सरकार को सत्ता से हटाना है ताकि वहां के लोगों को जुल्म से आजादी मिल सके। उन्होंने कहा कि ईरानी लोगों को आजाद कराना ही उनका असली लक्ष्य है।

**ईरान पर होंगे सबसे जोरदार हमले**

पेंटागन में पत्रकारों से बात करते हुए हेगसेथ ने कहा कि आज ईरान पर सबसे जोरदार हमले होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों में ईरान ने अब तक की सबसे कम मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी सेना के जनरल डैन केन ने जानकारी दी कि ईरान के खिलाफ यह सैन्य अभियान अब 11वें दिन में पहुंच गया है।

**क्षेत्रीय तनाव बढ़ा**

क्षेत्र के अन्य देशों में भी तनाव बढ़ गया है। कतर के खाद्य मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने अपनी तरफ आती एक मिसाइल को हवा में ही रोक दिया है। कतर ने अपने नागरिकों को ईरान के हमलों के डर से घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भी कहा है कि ईरान की तरफ से होने वाली फायरिंग को रोकने के लिए उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है।

वहीं इस सबके बीच, ईरान के एक सुरक्षा अधिकारी ने राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी भी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने भी दुनिया भर में हलचल मचा दी है। उन्होंने युद्ध कितने समय तक चलेगा, इस बारे में अलग-अलग संकेत दिए हैं। इस अनिश्चितता की वजह से सोमवार को शेयर बाजार और तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। इस बीच, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर कालीबाफ ने उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि तेहरान ने युद्ध रोकने (सीजफायर) की मांग की है।

**अमेरिकी सैन्य अधिकारी दे दिया बड़ा बयान**

वहीं इस सबके बीच अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में अमेरिकी सेना के तीन मुख्य लक्ष्य हैं। जनरल केन ने बताया कि अमेरिका का पहला मकसद ईरान की मिसाइलों को पूरी तरह नष्ट करना है। दूसरा बड़ा लक्ष्य ईरान की नौसेना (नेवी) पर हमला करना है। इसके अलावा, तीसरा मकसद ईरान के सैन्य ठिकानों (मिलिट्री बेस) के और भी अंदर तक घुसकर कार्रवाई करना है। जनरल केन के इस बयान से साफ है कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और भी तेज करने की तैयारी में है।अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई शांति से रह पाएंगे। मोजतबा, अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ट्रंप ने यह भी कहा कि इस बात की संभावना है कि वह ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन यह शर्तों पर निर्भर करेगा। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। सोमवार शाम को ईरान के साथ बातचीत की संभावना पर ट्रंप से सवाल पूछा गया। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, मैंने सुना है कि तेहरान बातचीत करना चाहता है। ट्रंप ने पहले कहा था कि ईरान के खिलाफ युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला है। हालांकि, उन्होंने कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई थी।

# वोटरों को धमकाया तो खैर नहीं, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सीईसी की नेताओं को सख्त चेतावनी

कोलकाता। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि बंगाल में किसी भी चुनावी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की यहां लगातार दो दिनों तक गहन समीक्षा के बाद कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल के मतदाताओं को आश्वस्त किया कि आगामी विधानसभा चुनाव पूरी तरह हिंसा रहित और दबाव रहित वातावरण में संपन्न होंगे।

**राजनीतिक दलों को साफ संदेश**

राजनीतिक दलों और नेताओं को उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव आयोग किसी भी स्तर पर मतदाताओं या किसी भी चुनाव अधिकारी को डराने या धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर आयोग संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि मतदाता भय मुक्त वातावरण में मतदान कर सकें इसके लिए पूरे राय भर में बहुत सूक्ष्म तरीके से केंद्रीय बलों की पर्याप्त तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने व्यापक सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्था की योजना बनाई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार के चुनाव में राय के सभी 80,000 से अधिक मतदान केंद्रों (बूथों) पर 100 प्रतिशत लाइव वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी, ताकि दिल्ली और कोलकाता में बैठे अधिकारी सीधे मतदान प्रक्रिया पर नजर रख सकें। वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता या दबाव की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बंगाल में कितने चरणों में चुनाव होंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह यहां की कानून व्यवस्था पर निर्भर करेगा। कानून- व्यवस्था की अंतिम समीक्षा के बाद ही चरणों का निर्धारण किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि राय में चुनाव के लिए अनुकूल माहौल है।

**आयोग हर राजनीतिक बयान का जवाब नहीं देता**

चुनाव आयोग के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग हर राजनीतिक बयान का जवाब नहीं देता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग संविधान व कानून से चलता है।

**एक भी वैध मतदाता का नाम नहीं छूटेगा**

एसआइआर में जिन मतदाताओं का नाम विचाराधीन श्रेणी में रखा गया है, इसपर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इन मामलों को न्यायिक अधिकारी देख रहे है और इसका तेजी से निपटारा किया जा रहा है।

लंबित या विचाराधीन 60 लाख से अधिक नामों के सत्यापन पर उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त समय है और सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से बाहर न रहे।

मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से एक पारदर्शी मतदाता सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि वैध मतदाताओं या नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी वैध मतदाता का नाम छूट या कट गया है अथवा मतदाता सूची में नहीं है तो वे फार्म छह भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ नए सिरे से आवेदन करें। उनका नाम शामिल हो जाएगा।

**सुरक्षा स्थिति और चुनावी तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया**

तीन दिवसीय दौरे के अंतिम दिन

आयोग की फुल बेंच ने राज्य की सुरक्षा स्थिति और चुनावी तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनावी समीक्षा के दौरान यहां के सभी राजनीतिक दलों, राज्य सरकार के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों और सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों (डीएम- एसपी) ने उन्हें आश्वस्त किया है कि चुनाव हिंसा रहित व बिना किसी दबाव में होगा। संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ चुनाव आयुक्त विवेक जोशी, सुखबीर सिंह संधू और राय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल भी मौजूद रहे। सूत्रों की मानें तो दिल्ली वापस लौटने के बाद आयोग 15 या 16 मार्च के आसपास चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है।

**चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए हाई-टेक इंतजाम**

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग ने इस बार चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई नए और कड़े कदम उठाए हैं। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो- पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पहली बार ईवीएम मशीन पर उम्मीदवारों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के बजाय रंगीन फोटो का इस्तेमाल किया जाएगा।

साथ ही, चुनाव के सात दिनों के भीतर किसी भी उम्मीदवार को ईवीएम की जांच कराने की अनुमति होगी। हर बूथ पर वेब-कास्टिंग- राय के सभी 80,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर वेब-कास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि दिल्ली और कोलकाता में बैठे अधिकारी सीधे मतदान प्रक्रिया पर नजर रख सकें। मतदान प्रतिशत का लाइव अपडेट- ईसीआई-नेट ऐप और आयोग की वेबसाइट पर हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत अपडेट किया जाएगा।

**मतदाताओं की सुविधा का रखा जाएगा खयाल**

ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता ही होंगे, ताकि भीड़ न बढ़े। हर बूथ पर वोटर सहायता केंद्र बनाया जाएगा और मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल रखने के लिए सुरक्षित स्थान भी सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए कालेजों में आयोग द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

# न्यायिक अधिकारियों के काम में बाधा न हो, सुप्रीम कोर्ट ने दिए बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने राय सरकार और चुनाव आयोग से कहा है कि न्यायिक अधिकारियों को अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए उचित और निर्बाध परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं। तीन जजों की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे, ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में तैनात न्यायिक अधिकारियों ने अब तक मतदाता सूची से हटाए जाने के खतरे का सामना कर रहे लोगों की 10.16 लाख आपत्तियों और दावों पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई भी नया अधिकारी कदम तब तक लागू न किया जाए, जब तक उसे कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी न मिल जाए। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग के पोर्टल में आने वाली तकनीकी दिक्कतों को तुरंत दूर किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आगे ऐसी समस्याएं न हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक अधिकारियों के लिए नए लॉग-इन आईडी जरूर बनाए जाएं, ताकि मतदाता सूची के संशोधन का काम बिना बाधा जारी रह सके। साथ ही स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियों के फैसलों की समीक्षा चुनाव आयोग के किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपीलों की सुनवाई के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की एक पीठ गठित कर सकते हैं। अदालत ने चुनाव आयोग को इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कई याचिकाओं के समूह पर कर रहा था।